विजेंदर जैन, सी.जे., एम.एम. कुमार, जसबीर सिंह, राजीव भल्ला और राजेश बिंदल, जे.जे. *के समक्ष*

मिहान और एक अन्य, - अपीलकर्ता

बनाम

इंदर और अन्य, - प्रतिवादी

आर.एस.ए. 1977 की संख्या 528

27 फरवरी, 2008

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-एस.एस.6, 14 और 30-पंजाब संशोधन अधिनियम, 1973-पंजाब कानून अधिनियम, 1872-एस.5-पिता द्वारा अपने दोनों के पक्ष में सहमति डिक्री के अनुसरण में किए गए भूमि के हस्तांतरण की वैधता के संबंध में विवाद बेटे - तीसरे बेटे द्वारा चुनौती - क्या पिता सहमति डिक्री के माध्यम से दो बेटों तक सीमित करके अपने हाथों में संपत्ति को अलग करने का हकदार है -क्या उत्तराधिकारी के हाथों में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति के रूप में माना जाएगा और इसके हस्तांतरण को हिंदू कानून के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा या संपत्ति केवल पैतृक है जैसा कि प्रथागत कानून के अनुसार जाना जाता है और हस्तांतरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है-पंजाब में संपत्ति को सहदायिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और इसके हस्तांतरण को हिंदू कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह 1956 अधिनियम की धारा 6 और 30 द्वारा विनियमित है-जैसा कि प्रथागत कानून में ज्ञात है, हरियाणा में संपत्ति को सहदायिक के साथ-साथ पैतृक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और इसके हस्तांतरण को हिंदू कानून और प्रथागत कानून दोनों के तहत चुनौती दी जा सकती है।

अभिनिर्णीत, कि जोगिंदर सिंह कुंधा सिंह बनाम केहर सिंह दसौंधा सिंह, एआईआर 1965 पंजाब 407 और प्रीतम सिंह बनाम सहायक नियंत्रक संपत्ति शुल्क, पटियाला, 1976 पीएलआर 342 में दिए गए पूर्ण पीठ के फैसलों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि एक मामले में न्यायालय को संपत्ति के हस्तांतरण के मुद्दे पर निर्णय लेने से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी और दूसरे मामले में मामला पूरी तरह से उत्तराधिकार के सवाल पर निर्भर था। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यद्यपि हस्तांतरण का मुद्दा किसी भी स्थिति में उत्तराधिकार के मुद्दे पर प्रभाव डाल सकता है, फिर भी तथाकथित संघर्ष की स्थिति में, कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि हस्तांतरण का मुद्दा अंततः जोगिंदर सिंह के मामले में उत्तराधिकार के बिंदु को गले नहीं लगा सका।

(पैरा 36)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया कि पंजाब राज्य के संबंध में पंजाब संशोधन अधिनियम, 1973 के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि पैतृक या गैर-पैतृक अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती देने पर पूर्ण प्रतिबंध है कि ऐसा स्थानांतरण या नियुक्ति रीति-रिवाज के विपरीत थी। पंजाब में, उत्तराधिकारी के हाथ में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और

इसके हस्तांतरण को हिंदू कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 30 द्वारा विनियमित है।

(पैरा 37)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया कि हरियाणा में, उत्तराधिकारी के हाथों में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति के साथ-साथ पैतृक संपत्ति भी माना जा सकता है, जैसा कि प्रथागत कानून के अनुसार जाना जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि पक्षकार यह स्थापित करने में विफल रहते हैं कि निर्णय का नियम परंपरा है तो वे हिंदू कानून का सहारा ले सकते हैं। इसलिए, हरियाणा में हिंदू कानून और प्रथागत कानून दोनों के तहत, हस्तांतरण को चुनौती दी जाएगी। उन सभी स्थितियों पर विचार करना आसान नहीं है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर हस्तांतरण के संबंध में प्रथागत कानून के विपरीत हिंदू कानून के आवेदन से सामने आएंगी।

(पैरा 38)

एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अलका सरीन, अधिवक्ता के साथ।
एस. डी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, बलबीर सिंह, अधिवक्ता, और अनुपम शर्मा, अधिवक्ता के साथ।
एम. एस. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदर्श जैन, अधिवक्ता के साथ।
संजय मजीठिया, अधिवक्ता ।
सुश्री मनीषा गांधी, अधिवक्ता।
सचिन सूद, अधिवक्ता।
अरुण जैन, अधिवक्ता।
सुकांत गुप्ता, अधिवक्ता।
पीएन अग्रवाल, अधिवक्ता।
एच. एस. मत्तेवाल, एडवोकेट जनरल, पंजाब, ए. जी. मसीह, सीनियर डीएजी, पंजाब के साथ हवा सिंह हुडा, महाधिवक्ता, हरियाणा, साथ में रामेश्वर मलिक, अतिरिक्त। एजी. हरयाणा।

निर्णय

एम. एम. कुमार, जे

(1) ये पाँच नियमित द्वितीय अपीलें हैं, अर्थात्, आर.एस.ए. 1977 की संख्या 528, 1982 की 2134, 1987 की 540, 1987 की 1656 और 1998 की 411, जिन्हें पहले की दो 3 जज बेंचों के बीच टकराव को देखते हुए इस पांच जजों वाली बेंच को भेजा गया है।
जोगिंदर सिंह कुंधा सिंह बनाम केहर सिंह दसौंधा सिंह,[1] और प्रीतम सिंह बनाम असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एस्टेट ड्यूटी, पटियाला[2] के मामले में संदिग्ध संघर्ष को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल द्वारा 25 अप्रैल, 1980 के संदर्भ आदेश, 1979 के आर.एस.ए. नं. 105 में पारित संदर्भ आदेश में इंगित किया गया है।

(2) सबसे पहले, सबसे पहले उस मुद्दे पर ध्यान देना उचित होगा जिस पर दो पूर्ण पीठों के बीच टकराव की बात कही गई है। उपर्युक्त विरोधाभास को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल (जैसा कि वह तब थे) ने अपने संदर्भ आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 1980 में देखा है, जिसे विस्तार से पढ़ा जाना आवश्यक है। संदर्भ आदेश 1979 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 105 (माई सिंह बनाम जस्सा सिंह और अन्य) में दर्ज किया गया था। अंततः उन अपीलों को वापस ले

[1] AIR 1965 Pb. 407
[2] 1976 PLR 342

लिया गया लेकिन संदर्भ तत्काल अपीलों में पढ़ा गया है। वहां विवाद पिता द्वारा अपने दो बेटों के पक्ष में सहमति डिक्री के अनुसरण में किए गए भूमि हस्तांतरण की वैधता को लेकर था। तीसरे बेटे ने उपरोक्त सहमति डिक्री को चुनौती दी थी। प्रश्न यह उठा कि क्या पिता को सहमति डिक्री के माध्यम से अपने हाथों की संपत्ति को दो बेटों तक सीमित करके अलग करने का अधिकार है। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश द्वारा देखा गया मूल विवाद यह था कि क्या पिता के हाथ में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति माना जाना चाहिए और इसका विकल्प हिंदू कानून के प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहिए।
तीसरे बेटे द्वारा दावा किया गया था या वह संपत्ति केवल पैतृक संपत्ति थी जैसा कि प्रथागत कानून के अनुसार जाना जाता है और इसलिए, इसका हस्तांतरण चुनौती के लिए खुला नहीं था। यह उपर्युक्त संदर्भ में है कि प्रश्न को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित टिप्पणियां 25 अप्रैल, 1980 के संदर्भ आदेश में की गई थीं, जो इस प्रकार है: - "यह विवादित नहीं है कि पार्टियां जाट हैं जो मुख्य रूप से एक कृषि जनजाति हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले प्रथागत कानून द्वारा शासित थीं।" इस न्यायालय की हालिया पूर्ण पीठ के अनुसार, **प्रीतम सिंह बनाम द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ इस्टेट ड्यूटी पटियाला, 1976 पी.एल.आर. 342,** 'उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद सिख जाटों के हाथ में संपत्ति सहदायिक संपत्ति होगी। हालाँकि, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने **जोगिंदर सिंह कुंधा सिंह बनाम केहर सिंह दसौंधा सिंह और अन्य, ए.आई.आर**. 1965 पंजाब 407 में पहले के पूर्ण पीठ मामले पर यह निर्धारित किया, जिसमें यह माना गया था कि कस्टम गवर्निंग हस्तांतरण के नियम प्रवर्तन से प्रभावित नहीं थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अभी भी प्रथा द्वारा शासित व्यक्तियों द्वारा हस्तांतरण को नियंत्रित करना जारी है। हालाँकि यह निर्णय बाद के पूर्ण पीठ मामले में देखा गया था, लेकिन इसे प्रासंगिक नहीं माना गया क्योंकि यह प्रथा द्वारा शासित किसी व्यक्ति की हस्तांतरण की शक्ति से संबंधित था। विद्वान वकील का आग्रह है कि हस्तांतरण की शक्ति की प्रकृति और सीमा में दो कानूनों, यानी हिंदू कानून और प्रथागत कानून के तहत कुछ बुनियादी अंतर हैं। यदि हस्तांतरण को कस्टम के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना है तो हस्तांतरण को किसी भी संपार्श्विक या विक्रेता के सामान्य पूर्वज से जुड़े व्यक्ति द्वारा पांचवीं डिग्री के भीतर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हस्तांतरण विक्रेता के जीवनकाल के दौरान वैध होगा। दूसरी ओर, यदि हस्तांतरण को हिंदू कानून द्वारा शासित किया जाना है, तो इसे केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब संपत्ति सहदायिक संपत्ति हो, वह भी केवल सहदायिक द्वारा और विक्रेता के लिए भी हस्तांतरण शून्य होगा। पैतृक और सहदायिक संपत्ति की अवधारणा भी कानून के दो स्कूलों के तहत अलग-अलग है। यदि एक बार यह माना जाता है कि कृषक द्वारा बनाए गए कस्टम गवर्निंग हस्तांतरण के नियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यदि संपत्ति पैतृक है तो हस्तांतरण को चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि प्रथागत कानून के मध्य में उस व्यक्ति द्वारा जाना जाता है जो पांचवीं डिग्री के भीतर संपार्श्विक है। उदाहरण के लिए, एक भाई अपने अन्य भाइयों से अलग होते हुए भी, उस संपत्ति के हस्तांतरण को चुनौती देने में सक्षम होगा जो दोनों भाइयों को हस्तांतरित हुई थी लेकिन उनके बीच हस्तांतरण से पहले विभाजित हो गई थी। यदि ऐसा है तो प्रथागत कानून द्वारा शासित किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस स्थिति में जिस क्षण दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ, वह सहदायिक संपत्ति नहीं रह गई और भाई ऐसी संपत्ति के दूसरे भाई द्वारा किए गए हस्तांतरण को चुनौती देने का हकदार नहीं होगा।

प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि फिलहाल किसी विशेष व्यक्ति के हाथों में संपत्ति की प्रकृति से निपटने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति पैतृक संपत्ति या सहदायिक संपत्ति बनी रहेगी क्योंकि यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले रही होगी। सहदायिक संपत्ति की अवधारणा, जो प्रथागत कानून द्वारा शासित कृषि जनजातियों के लिए अज्ञात थी, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह हिंदू

उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से लागू हो गई है जो केवल संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम केवल मृत हिंदू की संपत्ति के निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। विरासत में मिली संपत्ति पर उत्तराधिकारियों के क्या अधिकार हैं, जहां तक पुरुष उत्तराधिकारियों का सवाल है, इस अधिनियम का इससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन महिलाओं के मामले में, उन्हें ऐसी संपत्ति का पूर्ण मालिक बना दिया गया है। इसलिए, उक्त अधिनियम के तहत विरासत में मिली संपत्ति में पुरुष हिंदुओं के अधिकार पहले की तरह हिंदू कानून या रीति-रिवाज के नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे, केवल एक अपवाद के साथ कि एक पुरुष हिंदू अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के आधार पर को सहदायिक संपत्ति में अपने हिस्से को वसीयत द्वारा निपटाने की निरंकुश शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो अधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले उनके पास नहीं था। पुनः, पंजाब कानून अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के आधार पर, हस्तांतरण के मामलों में पंजाब और हरियाणा में कृषक रीति-रिवाज के नियमों द्वारा शासित होते हैं, न कि हिंदू कानून के द्वारा। पहले पूर्ण पीठ मामले के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा रीति-रिवाज के नियमों को निरस्त नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि उक्त अधिनियम में रीति-रिवाज के नियमों के विपरीत प्रावधान किया गया है। इसलिए, एक कृषक को विरासत में मिली संपत्ति में अधिकारों की प्रकृति से संबंधित रीति-रिवाज के नियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद भी लागू रहेंगे। विद्वान वकील के तर्क में कुछ तथ्य प्रतीत होते हैं, लेकिन किसी भी मामले में ऊपर देखे गए दो पूर्ण पीठ के फैसलों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है क्योंकि कानून के दो प्रस्ताव हैं कि एक व्यक्ति हस्तांतरण के मामलों में प्रथागत कानून द्वारा शासित होता है और वह उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली संपत्ति सहदायिक संपत्ति है, जो संभवतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले रीति-रिवाजों के नियमों द्वारा शासित किसी व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती है। इसलिए, इस मामले का रिकॉर्ड उक्त दो पूर्ण पीठों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है।

(3) तदनुसार, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ दिया गया था। जब 28 अगस्त, 1981 को पूर्ण पीठ की बैठक हुई, तो उसने उस वकील के तर्क पर ध्यान दिया, जिसने न्यायिक औचित्य के हित में एक बड़ी पीठ द्वारा प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए प्रचार किया था। 28 अगस्त, 1981 को तीन जजों की बेंच द्वारा मामले को पांच जजों की बेंच को रेफर करते हुए पारित आदेश इस प्रकार है:-

"**एस.एस. संधवालिया, सी.जे**.

अभी भी बड़ी पीठ के इस संदर्भ के लिए, तथ्यों को चित्रित करना या मुद्दे को विस्तृत करना अनावश्यक है क्योंकि पूर्ण पीठ के पहले के संदर्भ को इसका अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। हालाँकि, शुरुआत में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह तथ्य है कि काफी महत्व के मुद्दे के लिए, बल्कि असामान्य रूप से, हमें उत्तरदाताओं की ओर से किसी भी तर्क का लाभ नहीं मिला। श्री एस. पी. गुप्ता, उनके विद्वान वकील ने तुरंत प्रार्थना की थी कि वह मामले से हटना चाहते हैं और बार में बताए गए कारणों के आधार पर, हमने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अशोक भान ने स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रुख अपनाते हुए कहा कि वास्तव में **जोगिंदर सिंह कुंधा सिंह बनाम केहर सिंह दसौंधा सिंह और अन्य, ए.आई.आर. 1965 पंजाब 407, और प्रीतम सिंह बनाम द असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ इस्टेट ड्यूटी, पटियाला,** 1976 पी.एल.आर. 342 मामले में इस न्यायालय की दो पूर्ण पीठ के फैसले में कुछ मतभेद दिखाई दिए।

दबाव डालने पर भी, विद्वान वकील ने पिछली पूर्ण पीठ को बाद की पूर्ण पीठ से सार्थक रूप से अलग करने में अपनी असमर्थता स्वीकार की। यद्यपि वकील ने **प्रीतम सिंह के मामले** (सुप्रा) में दृष्टिकोण की स्वीकृति के लिए प्रचार किया, लेकिन वह यह कहने में काफी निष्पक्ष थे कि न्यायिक औचित्य की मांग है कि उस दृष्टिकोण की पुष्टि एक बड़ी पीठ द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि उनके अनुसार, इसके विपरीत टिप्पणियाँ थीं , दोनों **जोगिंदर सिंह कुंधा सिंह के मामले** में (सुप्रा), और **अमर सिंह और अन्य बनाम सीव ए राम और अन्य**, 1960 पंजाब 530 में इससे भी पहले की पूर्ण पीठ में। इस प्रकार यह अपरिहार्य प्रतीत होता है कि इस मामले पर अब एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, यहां मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका प्रभाव इतना अधिक है कि एक बहुत ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि इस मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाए।

(एसडी / -)
एस. एस. संधवालिया
मुख्य न्यायाधीश.

(एसडी / -)
प्रेम चंद जैन,
न्यायाधीश.

(एसडी / -)
एस. पी. गोयल,
न्यायाधीश.

28 अगस्त. 1981"

(4) श्री एम.एल. सरीन और श्री एस.डी. शर्मा, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हवा सिंह हुडा और श्री एच.एस. मत्तेवाल, क्रमशः विद्वान महाधिवक्ता हरियाणा और पंजाब, और श्री पी.एन. अग्रवाल ने तर्क दिया है कि हिंदू कानून कई स्रोतों से प्रवाहित होता है जिसमें स्मृति और धर्मशास्त्र, कानून, प्रथा या उपयोग और यहां तक कि न्यायिक मिसालें भी शामिल हैं। विद्वान वकील के अनुसार जहां पक्ष हिंदू हैं, वे हिंदू कानून या प्रथागत कानून द्वारा शासित होते हैं, बशर्ते कि यह प्रथा इसके प्रवर्तकों द्वारा कानून के अनुसार साबित की गई हो। उन्होंने आगे कहा है कि हिंदू कानून भी संहिताकरण से प्रभावित हुआ है और उस हद तक यह इस तरह के कानून द्वारा संशोधित है। तर्क यह प्रतीत होता है कि हिंदू कानून अभी भी उन क्षेत्रों को

छोड़कर लागू होता है जहां क्षेत्र कानून द्वारा कब्जा कर लिया गया है या ऐसे हिंदू कानून को कस्टम द्वारा संशोधित किया गया है। यह माना जाता है कि उत्तराधिकार अधिनियम का उसकी धारा 4 के अनुसार अधिभावी प्रभाव होना चाहिए और उस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू होने वाले किसी भी पाठ, हिंदू कानून की व्याख्या के नियम या उस कानून के पक्ष के रूप में किसी भी प्रथा या उपयोग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले के संबंध में प्रभाव होगा जिसके लिए उस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 को उन वर्षों के आसपास संहिताबद्ध अन्य सभी हिंदू संहिताओं में दोहराया गया है और उस संबंध में संदर्भ दिया गया है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 4, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और साथ ही हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 5। विद्वान वकील ने प्रीतम सिंह के मामले की पूर्ण पीठ से विभिन्न पैराओं को संदर्भित और पढ़ा है (सुप्रा) उपरोक्त प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए।

(5) उन्होंने आगे बताया है कि उत्तराधिकार अधिनियम मुख्य रूप से हिंदुओं के बीच निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित है, हालांकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 भी वसीयत उत्तराधिकार का प्रावधान करती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम हस्तांतरण से संबंधित नहीं है और इसलिए, हस्तांतरण से संबंधित हिंदू कानून और प्रथागत कानून जीवित हैं। उन्होंने आगे बताया है कि उत्तराधिकार अधिनियम प्रत्यावर्तनकर्ता को समाप्त नहीं करता है और वे संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के संबंध में किए गए किसी भी हस्तांतरण को चुनौती देने के अपने अधिकार के साथ जारी रहेंगे। विद्वान वकील के अनुसार जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ का फैसला हस्तांतरण से संबंधित है और इसने कौर सिंह (सुप्रा) के मामले में उस संबंध में पिछली डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणी को मंजूरी दे दी है। श्री सरीन ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कौर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय **दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह**,[3] के मामले में भी स्वीकार किया गया है। दर्शन सिंह के मामले (सुप्रा) में विद्वान वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कानून अधिनियम, 1872 की धारा 5, पंजाब सीमा (कस्टम) अधिनियम, 1920 और पंजाब कस्टम (प्रतिवाद करने की शक्ति) अधिनियम, 1920 और ने निष्कर्ष निकाला है कि पंजाब कस्टम (प्रतिवाद करने की शक्ति) संशोधन अधिनियम, 1973 की धारा 7, पैतृक या गैर-पैतृक अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती देने पर पूरी तरह रोक लगाती है कि ऐसा हस्तांतरण या नियुक्ति रीति-रिवाज के विपरीत थी। आगे यह माना गया है कि प्रावधान में इस्तेमाल की गई भाषा इस प्रथा के निरंतर अस्तित्व के साथ असंगत है। विद्वान वकील के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि "कोई भी व्यक्ति किसी भी हस्तांतरण का विरोध इस आधार पर नहीं करेगा कि ऐसा हस्तांतरण प्रथा के विपरीत है"। श्री सरीन के अनुसार इस प्रथा को पूरी तरह से मिटा कर खत्म कर दिया गया है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को प्रथा के विपरीत होने के आधार पर अचल संपत्ति, चाहे पैतृक हो या गैर-पैतृक, के किसी भी हस्तांतरण का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रावधान को सभी लंबित कार्रवाइयों पर लागू माना गया है, चाहे वह मुकदमे के चरण में हो या अपीलीय अदालत के स्तर पर, इस तर्क पर कि अपील मुकदमे की निरंतरता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम ने पंजाब में हिंदू कानून में किए गए प्रावधानों के अलावा पुरुष मालिक द्वारा हस्तांतरण पर प्रतिबंध से संबंधित किसी भी नियम या प्रथागत

---

[3] **1992 Suppl.(l) SCC 191**

कानून को निरस्त नहीं किया है। ऐसे किसी भी हस्तांतरण को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने के लिए हिंदू कानून में शामिल लोगों के अलावा प्रत्यावर्तनकर्ताओं का अधिकार मौजूद रहा और इन परिस्थितियों में इस तरह के हस्तांतरण का विरोध करने के अधिकार को समाप्त करना आवश्यक समझा गया और 1973 के अधिनियम को सही ठहराया गया है। अपनाया।

(6) हालाँकि, हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री हवा सिंह हुडा ने बताया है कि हरियाणा में पंजाब सीमा शुल्क (प्रतिवाद करने की शक्ति) अधिनियम, 1920 या पंजाब सीमा (सीमा शुल्क) अधिनियम, 1920, समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। जैसा कि पंजाब राज्य द्वारा किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, हरियाणा राज्य में स्थिति वैसी ही बनी रहेगी और सहदायिक संपत्ति या हिंदू अविभाजित पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण को 1920 के दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रथा साबित करके चुनौती दी जा सकती है। विद्वान महाधिवक्ता के अनुसार, हरियाणा में, हिंदू कानून उन पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करना जारी रखेगा जो संहिताबद्ध कानून और विधान और रीति-रिवाज के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़कर हिंदू हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने कहा है कि दर्शन सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हरियाणा राज्य में कोई आवेदन नहीं होगा।
(7) हालाँकि, सभी विद्वान वकीलों ने एक ही तर्क दिया है कि दोनों पूर्ण पीठों में कोई टकराव नहीं है क्योंकि दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। श्री एस.डी. शर्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने कहा है कि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी हिंदू संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानूनों के नियमों द्वारा शासित नहीं होगा, जैसा कि धारा 2 और 4 द्वारा प्रदान किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, सभी हिंदू जो पहले अन्य हिंदुओं की तरह उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित थे, उन्हें संयुक्त और अविभाजित हिंदू परिवार बनाना होगा और संयुक्त संपत्ति के धारक के पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों को जन्म से उसमें ब्याज प्राप्त होगा। तदनुसार, 17 जून, 1956 तक लागू उत्तराधिकार के सभी नियम, जब उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ, हिंदू के किसी भी पाठ या नियम के आधार पर, उत्तराधिकार अधिनियम में निपटाए गए सभी मामलों के संबंध में निरस्त कर दिए गए। उत्तराधिकार अधिनियम ने अपने लागू होने से तुरंत पहले लागू होने वाले किसी भी केंद्रीय राज्य कानून में निहित किसी भी अन्य कानून को भी खत्म कर दिया, जहां तक कि उत्तराधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप ऐसा कानून है। श्री शर्मा ने फिर जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में फैसले के अनुपात का उल्लेख किया, जो धारा 14 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है और पूर्ण पीठ धारा 14 के अनुसार, जिसने विधवा की संपत्ति में वृद्धि की है, वह भेदभाव के दोष से ग्रस्त नहीं है लिंग के आधार पर और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। विद्वान वकील के अनुसार, निर्णय उत्तराधिकार के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यह बनाए रखा गया है कि निर्णय का अनुपात निर्णायक यह है कि उत्तराधिकार अधिनियम ने पुनरीक्षकों को समाप्त नहीं किया है, जो ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी विशेष व्यक्ति द्वारा रखी गई संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। प्रथा के अनुसार केवल संपार्श्विक (5 डिग्री के भीतर प्रत्यावर्तनकर्ताओं को पुरुष मालिक के हस्तांतरण को चुनौती देने या नियंत्रित करने का हकदार माना गया है और उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि हस्तांतरण को नियंत्रित करने की उनकी शक्ति का अस्तित्व समाप्त हो गया है। हालाँकि, प्रत्यावर्तक अब किसी महिला द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण को चुनौती देने के हकदार नहीं हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराधिकार

अधिनियम लागू होने के बाद एक महिला द्वारा रखी गई संपत्ति एक पूर्ण संपत्ति में बढ़ जाती है। अत: स्त्री की परायेपन की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह बताया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में किए गए हालिया संशोधन के आधार पर महिला को सहदायिक के रूप में मान्यता देने से उसकी स्थिति और बेहतर हुई है। इसलिए आग्रह किया गया है कि दोनों पूर्ण पीठ अलग-अलग क्षेत्रों में काम करें। प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ उत्तराधिकार से संबंधित है, जबकि जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ हस्तांतरण से संबंधित है। (8) दो पूर्ण पीठ के निर्णयों के आलोक में, दो मुख्य मुद्दे जो पहले उठाए गए हैं हम इस प्रकार हैं:-

(1) क्या जोगिंदर सिंह (सुप्रा) और प्रीतम सिंह (सुप्रा) के मामलों में दिए गए इस न्यायालय के दो निर्णयों के बीच कोई वास्तविक विरोधाभास है?

(2) क्या उत्तराधिकारी के हाथों में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति माना जाएगा और उसका हस्तांतरण हिंदू कानून द्वारा शासित होगा या उत्तराधिकारी के हाथों में मौजूद संपत्ति केवल पैतृक संपत्ति है, जैसा कि प्रथागत कानून और उसके हस्तांतरण से ज्ञात होता है , इसलिए, चुनौती के लिए खुला नहीं है?

(9) उपरोक्त दो आदेशों से, जिसके कारण पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन हुआ, यह सामने आया कि यह सबसे पहले आवश्यक है जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) और प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में पहले की दो तीन-न्यायाधीश पीठों में दिए गए प्रस्ताव (प्रस्तावों) के महत्व को समझने के लिए।

(10) उपर्युक्त अभ्यास इस कारण से किया जाना आवश्यक है कि यह किसी निर्णय का केवल अनुपातिक निर्णय है जो बाध्यकारी चरित्र का है न कि ओबिटर डिक्टम का। किसी निर्णय को समग्र रूप से पढ़ने पर, न्यायालय के समक्ष प्रश्नों के आलोक में, यह सिद्धांत सामने आता है जो अनुपात बनाता है, न कि कोई विशेष शब्द या वाक्य। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी निर्णय में "घोषित कानून" है, इसे तब कानून नहीं कहा जा सकता जब किसी मुद्दे का निपटारा रियायत पर किया जाता है और जो बाध्यकारी है वह निर्णय का अंतर्निहित सिद्धांत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **निपटान निदेशक, ए.पी. बनाम एम.आर. अप्पाराव**,[4] के मामले प्रेक्षित किया है कि न्यायालय के निर्णय को उन प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो विचार के लिए उठे थे - जिस मामले में फैसला सुनाया गया. अनुपात निर्णय से भिन्न "ओबिटर डिक्टम" उसके समक्ष किसी मामले में सुझाए गए कानूनी प्रश्न पर न्यायालय द्वारा किया गया एक अवलोकन है, लेकिन इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है कि निर्णय की आवश्यकता हो। ऐसा ओबिटर एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा। इसी तरह की टिप्पणियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर,[5] और हमीद जौहरन बनाम अब्दुल सलाम,[6]** के मामलों में की गई हैं**। हरियाणा राज्य बनाम रणबीर**[7] के मामले में एक अन्य हालिया फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 12 में निम्नानुसार प्रेक्षित किया की है: -

"...एक निर्णय, यह अच्छी तरह से तय है, जो कुछ भी है उसके लिए एक प्राधिकारी है निर्णय लेता है न कि उससे तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। डिक्टा और ओबिटर के बीच का अंतर सर्वविदित है। ओबिटर डिक्टा निर्णय के लिए कमोबेश अनावश्यक है। यह किसी दृष्टिकोण या भावनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। एडीएम, जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, (1976) 2 एससीसी 521 देखें। यह भी अच्छी

---

[4] (2002) 4 SCC 638

[5] (1989) 1 SCC 101

[6] (2001) 7 SCC 573

[7] (2006) 5 SCC 167

तरह से स्थापित है कि जो बयान अनुपात निर्णय का हिस्सा नहीं हैं, वे ओबिटर डिक्टा का गठन करते हैं और आधिकारिक नहीं हैं। (डिवीजनल कंट्रोलर, केएसआरटीसी बनाम महादेव शेट्टी, (2003) 7 एससीसी 197 देखें)।" कानून के उपरोक्त कथन के आलोक में, अब हम जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) और प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में दो 3-न्यायाधीश पीठों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

(11) जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में, मूल विवाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षिप्तता के लिए, 'उत्तराधिकार अधिनियम') की धारा 14 की संवैधानिक वैधता के बारे में था और क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उपरोक्त हमले को पूर्ण पीठ ने निरस्त कर दिया था। पुरुष मालिक द्वारा किए गए उपहार विलेख की वैधता एक घोषणात्मक मुकदमा दायर करके प्रत्यावर्तक के उदाहरण पर चुनौती का विषय थी, जिसके कारण अंततः इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। पलटवारकर्ता ने वाद में आरोप लगाया था कि भूमि पैतृक थी और पक्ष कस्टम द्वारा शासित थे, जबकि संबंधित अपीलों में, पुरुष मालिक द्वारा किए गए बिक्री कार्य चुनौती का विषय थे। तथ्यों का पता लगाने पर, न्यायालयों ने पाया कि भूमि पैतृक थी और पुरुष मालिक द्वारा की गई बिक्री बिना किसी कानूनी आवश्यकता के थी। हालाँकि, दोनों मामलों में पुरुष मालिक द्वारा अपना बचाव यह किया गया था कि 'उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कारण, पुरुष मालिक की हस्तांतरण की शक्ति पर सीमा समाप्त हो गई थी और उलटने वालों को इस तरह के हस्तांतरण को चुनौती देने से रोक दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुकदमे खारिज कर दिए थे। अपील पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को यह कहते हुए उलट दिया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो किसी भी तरह से पुरुष मालिक के अधिकार को बढ़ा देता हो। जिस तरह से इसने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के आधार पर एक महिला के अधिकारों को बढ़ाया है, जो पूर्ण मालिक बन गई है। तदनुसार, यह माना गया कि पुरुष मालिक द्वारा रखी गई संपत्ति और उसकी हस्तांतरण की शक्ति पर सीमा को किसी भी तरह से नहीं हटाया गया था और उलटफेर करने वालों को ऐसे हस्तांतरण को चुनौती देने से नहीं रोका गया था। **कौर सिंह गज्जन सिंह बनाम जग्गर सिंह केशी सिंह**[8] के मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले के बाद, विद्वान सिंह न्यायाधीश ने निचली अपीलीय अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा, यह दोहराते हुए उत्तराधिकार अधिनियम में पुरुष धारक की संपत्ति को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था और पैतृक संपत्ति के निपटान की उसकी शक्ति पर सीमा वैसे ही जारी रही। यह देखा गया कि इसमें विसंगति हो सकती है, क्योंकि ऐसे पुरुष से महिला उत्तराधिकारी की शक्ति पूर्ण होनी चाहिए जबकि पुरुष मालिक की संपत्ति को अलग करने की शक्ति सीमित होनी चाहिए। इस विषम स्थिति को चुनौती देने के लिए मामले को लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष ले जाया गया और आग्रह किया गया कि इस तरह की व्याख्या के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 में बनाए गए समानता खंड का उल्लंघन होगा। तदनुसार, यह आग्रह किया गया कि कौर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पंजाब लिमिटेशन (कस्टम) एक्ट (नंबर 1 ऑफ 1920) और पंजाब कस्टम (पॉवर टू कॉन्टेस्ट) एक्ट (नंबर 2 ऑफ 1920) के प्रावधानों पर गौर करने के बाद, फुल बेंच ने देखा कि पुरुष धारक की शक्ति को अलग करने की शक्ति संपत्ति केवल तभी सीमित थी जब अस्तित्व में प्रत्यावर्तक थे जिनके संबंध में पुरुष धारक द्वारा रखी गई संपत्ति को पैतृक माना जा सकता था, जिसे उपरोक्त दो क़ानूनों द्वारा नियंत्रित किया गया था। यदि किसी व्यक्ति के पास पाँच डिग्री के

---

[8] **AIR 1961 Pb. 489**

भीतर रहने वाला कोई प्रतिवर्ती नहीं था, तो पैतृक संपत्ति के लिए उसकी हस्तांतरण की शक्ति उसकी स्व-अर्जित संपत्ति के साथ सह-विस्तारित थी।

(12) पूर्ण पीठ ने तब उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया और पाया कि इसने हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार का एक समान कोड लाया है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे पहले हिंदू कानून या प्रथागत कानून द्वारा शासित थे और उस सीमा तक हिंदू कानून और प्रथागत कानून दोनों को संशोधित या निरस्त कर दिया गया, जैसा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 द्वारा घोषित किया गया है। इसने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 पर ध्यान दिया, जिसने एक महिला की संपत्ति को उसके द्वारा अर्जित या पुरुष या महिला मालिक से विरासत में मिली संपत्ति में बढ़ा दिया। तदनुसार, पूर्ण पीठ ने माना कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 यह बताती है कि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले एक हिंदू महिला द्वारा विरासत या अन्यथा द्वारा रखी गई संपत्ति का विस्तार किया गया था और उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने की तारीख पर, वह एक बन गई। पूर्ण स्वामी. इसी तरह, अगर उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद उसे कोई संपत्ति विरासत में मिली है, तो उसे सीमित मालिक के बजाय पूर्ण मालिक माना जाएगा। नतीजतन, हस्तांतरण की शक्ति पर सीमाएं स्वतः ही गायब हो गईं। यह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में किये गये प्रावधानों का आवश्यक परिणाम था। पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि पुरुष मालिकों के संबंध में, पैतृक संपत्ति में उनकी संपत्ति को बढ़ाने या उनके द्वारा विरासत में मिली संपत्ति पर हस्तांतरण की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। हालाँकि, इसने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 पर ध्यान दिया और पाया कि यह केवल वसीयत द्वारा सहदायिक संपत्ति में उसके हिस्से की शक्ति से संबंधित है, उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले, उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में पुरुष मालिक के संबंध में एकमात्र प्रावधान उसकी इच्छा द्वारा हस्तांतरण की शक्ति थी। जहां तक, प्रथा द्वारा शासित व्यक्तियों का संबंध है, वे पुरुष धारक की हस्तांतरण की शक्ति पर प्रतिबंध द्वारा शासित होते रहे, जैसा कि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले मौजूद था। इसी प्रकार, वसीयत द्वारा निपटान के अलावा हस्तांतरण पर अन्य प्रतिबंध भी जारी रहे। इस प्रकार, पूर्ण पीठ ने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के आधार पर हिंदू महिलाओं के श्रेष्ठ अधिकार को मान्यता दी और प्रावधान को इंट्रावायर के रूप में बरकरार रखा। यह तर्क कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के लागू होने के बाद प्रत्यावर्तनकर्ताओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है, खारिज कर दिया गया क्योंकि उस प्रभाव का कोई प्रावधान नहीं बताया गया था। अमर सिंह बनाम सेवा राम,[9] के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला देते हुए तर्क को खारिज कर दिया गया था और अनुमोदन के साथ निम्नलिखित पैराग्राफ को पूर्ण पीठ द्वारा उद्धृत किया गया था: -

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उलटने वालों के अधिकारों को छीन लेता है। अधिनियम किसी भी तरह से उनके अधिकारों या स्थिति को वापस लेने वालों को समाप्त नहीं करता है। जहां संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और नियंत्रण है, वहां अधिनियम के पहले और बाद में कानून की स्थिति समान रहती है और अगला प्रत्यावर्तनकर्ता अपने प्रत्यावर्तन की सुरक्षा के लिए कानून में हकदार है।

[9] AIR 1960 Pb. 530 (F.B.)

(13) इसने आगे कहा कि संपार्श्विक द्वारा कोई भी मुकदमा यह घोषित करने के लिए सक्षम नहीं होगा कि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद अपने पति की बेटी के पक्ष में एक विधवा द्वारा दिया गया उपहार अमान्य है क्योंकि संपार्श्विक के पास अधिग्रहण का कोई मौका नहीं था चाहे संपत्ति पैतृक हो या स्व-अर्जित। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए संपार्श्विक का अस्तित्व समाप्त हो गया था या उनके पास हस्तांतरण को चुनौती देने का अधिकार नहीं था, जो कि उन्हें प्रथागत कानून के तहत प्राप्त अधिकार था। पूर्ण पीठ ने आगे कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के आधार पर, उत्तराधिकार अधिनियम में दिए गए उत्तराधिकार के नियमों को उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले अन्य सभी नियमों या कानूनों पर मिसाल लेनी होगी और वह उत्तराधिकार अधिनियम केवल उस सीमा तक प्रथा का स्थान लेता है जिस सीमा तक उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान किए गए हैं।

(14) पूर्ण पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि पैतृक संपत्ति को अलग करने के लिए पुरुष मालिकों की शक्ति को नियंत्रित करने वाली प्रथा को अनुचित घोषित किया जाना चाहिए और न्यायालयों को इसे लागू करने से इनकार कर देना चाहिए। पूर्ण पीठ ने एक वैध प्रथा की आवश्यकता का उल्लेख किया जैसा कि रैटिगन्स डाइजेस्ट ऑफ कस्टमरी लॉ के पैराग्राफ 1 में दिया गया है और निम्नानुसार कहा गया है: -

"बेशक, हस्तांतरण पर नियंत्रण के नियम को प्राचीन काल से ही न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है और लागू किया गया है और इसे न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विपरीत नहीं माना गया है। विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह था कि बदली हुई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप यह नियम पुरातन हो गया है और इसे न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विपरीत माना जाना चाहिए। अब, जैसा कि ऊपर खंड (डी) में बताया गया है, वैध होने के लिए एक प्रथा प्राचीन, निश्चित और अपरिवर्तनीय होनी चाहिए और इसलिए, नियम को केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जा सकता क्योंकि यह पुराना या पुरातन है। इसके अलावा इस नियम को सिर्फ इसलिए न्याय, समानता और अच्छे विवेक के विपरीत नहीं माना जा सकता क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मद्देनजर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह भेद निश्चित रूप से अनैतिक नहीं है और इसे सार्वजनिक नीति का विरोधी नहीं कहा जा सकता है।"

(15) जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रस्तावों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है: -

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने से पहले की स्थिति

(ए) पंजाब राज्य में उत्तराधिकार का अधिकार और हस्तांतरण की शक्ति व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होती है, अर्थात हिंदुओं के मामले में मिताक्षरा स्कूल के हिंदू कानून द्वारा, सिवाय उस हद तक जिस हद तक यह प्रथा द्वारा संशोधित है;

(बी) प्रथागत कानून के अनुसार भी उसे विरासत में मिली संपत्ति अंतिम पुरुष धारक की स्व-अर्जित संपत्ति थी या उसे अपने पूर्वज से विरासत में मिली थी;

(सी) पुरुष को कोई संपत्ति विरासत में मिलने के मामले में, जहां तक पैतृक संपत्ति का संबंध है, समान सीमाएं थीं, बशर्ते कि पांच डिग्री के भीतर रहने वाले कोई भी प्रत्यावर्तक हों जो पंजाब सीमा (कस्टम) अधिनियम 1920 और पंजाब कस्टम (असम्मति की शक्ति) अधिनियम, 1920 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर अनुचित हस्तांतरण को चुनौती दे सकें।;

(डी) यदि पांच डिग्री के भीतर कोई प्रत्यावर्तनकर्ता नहीं हैं, तो पैतृक संपत्ति के लिए भी हस्तांतरण की शक्ति स्व-अर्जित संपत्ति के साथ व्यापक थी;

(ई) हिंदू कानून द्वारा शासित व्यक्ति की शक्ति भी पैतृक संपत्ति तक ही सीमित थी, या जिसे सहदायिक संपत्ति कहा जाता है।

उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद की स्थिति - जोगिंदर सिंह के मामले में दिए गए प्रस्ताव

(ए) उत्तराधिकार अधिनियम ने हिंदुओं के बीच उत्तराधिकार की एक समान संहिता ला दी है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे पहले हिंदू कानून या रीति-रिवाज द्वारा शासित थे, और उस सीमा तक हिंदू कानून और प्रथागत कानून दोनों उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधिभावी प्रभाव के आधार पर संशोधित या निरस्त कर दिए गए।

(बी) किसी पुरुष मालिक द्वारा रखी गई संपत्ति और उसकी हस्तांतरण की शक्ति की सीमा को उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा किसी भी तरह से नहीं हटाया गया था और उलटफेर करने वालों को इस तरह के हस्तांतरण को चुनौती देने से नहीं रोका गया था। पूर्ण पीठ ने **कौर सिंह** के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले का पालन किया और उसे मंजूरी दी, जिसे **दर्शन सिंह** के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह हिंदू कानून है, किसी भी संपत्ति को विरासत में पाने वाली महिला के पास केवल वही संपत्ति होती है, जिसे विधवा की संपत्ति के रूप में जाना जाता है, और उसके हस्तांतरण का अधिकार सीमित है और वह केवल विचार और कानूनी आवश्यकता के लिए ही अलग हो सकती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माननीय यह नोटिस करना उचित है या नहीं। 'दर्शन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **बारा सिंह बनाम कश्मीरा सिंह**,[10] में लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को खारिज कर दिया है।

(सी) संपत्ति को हस्तांतरित करने की पुरुष धारक की शक्ति केवल तभी सीमित होती है, जब अस्तित्व में ऐसे प्रत्यावर्तक होते हैं जिनके संबंध में पुरुष धारक द्वारा रखी गई संपत्ति को पैतृक माना जा सकता है,

जिसे पंजाब सीमा (कस्टम) अधिनियम, 1920 और पंजाब सीमा शुल्क (प्रतियोगिता की शक्ति) अधिनियम, 1920 के आधार पर पांच डिग्री तक प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, यदि किसी पुरुष धारक के पास पाँच डिग्री के भीतर रहने वाला कोई प्रत्यावर्तक नहीं था, तो पैतृक संपत्ति के लिए उसकी हस्तांतरण की शक्ति उसकी स्व-अर्जित संपत्ति के साथ सह-व्यापक थी। पूर्ण पीठ ने संपत्ति में महिला हितों के विस्तार को भी निर्धारित किया - उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत सीमित संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व में तत्काल रूपांतरण, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हस्तांतरण की शक्ति पर प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन केवल उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ के समय उसके पास मौजूद संपत्ति के संबंध में। इसने आगे कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, पुरुष मालिकों द्वारा पैतृक संपत्ति के संबंध में अपनी संपत्ति का विस्तार करने या उन्हें विरासत में मिली संपत्ति पर हस्तांतरण की शक्ति बढ़ाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। धारा 30 के अनुसार, एक पुरुष मालिक को वसीयत द्वारा सहदायिक संपत्ति से निपटने की शक्ति प्राप्त है, उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।

(डी) उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को अंतर-आधिकारिक माना गया और इसके विपरीत तर्क कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, खारिज कर दिया गया।

---

[10] JT(1987) 2 S.C. 234

(ई) पूर्ण पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पैतृक संपत्ति को अलग करने के लिए पुरुष मालिकों की शक्ति को नियंत्रित करने वाली प्रथा को अनुचित घोषित किया जाना चाहिए और न्यायालयों को इसे लागू करने से इनकार कर देना चाहिए।

(16) यह निर्णय, मानो प्रीतम सिंह के मामले में पूर्ण पीठ के सामने आने वाली समस्या की प्रत्याशा को सही ठहराता है प्रथागत कानून के तहत "पैतृक संपत्ति" की अवधारणा हस्तांतरण की शक्ति के प्रयोग के मामले में हिंदू कानून के तहत "सहदायिक संपत्ति" की अवधारणा के समान है। निर्णय के पैरा 12 में यह निर्धारित किया गया है:-

"..... एक हिंदू सहदायिक की अपने जीवनकाल के दौरान ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्तियों पर सीमा जारी है और इस संबंध में हिंदू कानून द्वारा शासित व्यक्ति और कस्टम द्वारा शासित व्यक्ति बराबर हैं। इस प्रकार जहां तक जीवित प्राणियों के बीच हस्तांतरण के अधिकार का सवाल है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी हिंदू पुरुषों को उन लोगों की तुलना में कोई बेहतर अधिकार प्राप्त नहीं है जो प्रथा द्वारा शासित हैं और इस प्रकार किसी भी भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है..."

(17) यदि हस्तांतरण की शक्ति पर प्रतिबंधों की प्रकृति और सीमा प्रथागत कानून और हिंदू कानून दोनों के तहत समान या समान है, और दोनों प्रणालियों के तहत 'पैतृक संपत्ति' और 'सहदायिक संपत्ति' की अवधारणाएं भी समान हैं, फिर वर्तमान संदर्भ के तहत शायद ही कोई संघर्ष हो।

प्रीतम सिंह के मामले में फुल बेंच का फैसला

(18) प्रीतम सिंह (सुप्रा) के मामले में अन्य पूर्ण पीठ का फैसला, **संपदा शुल्क नियंत्रक, पंजाब बनाम हरबंस सिंह,**[11] के मामले में लिए गए पहले डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण के बारे में संदेह का परिणाम था।

(19) मुद्दे को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, सबसे पहले हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले और उसमें उठाए गए मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक होगा। उस मामले में, पंजाब के एस्टेट ड्यूटी के सहायक नियंत्रक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद तीन बेटों को जवाबदेह व्यक्ति मानते हुए उनके संबंध में एक मूल्यांकन तैयार किया और उनकी पूरी संपत्ति का मूल्यांकन एस्टेट ड्यूटी के लिए किया गया था। आगे की अपील पर, जोनल अपीलीय नियंत्रक ने भी मूल्यांकन अधिकारी की तरह पाया कि मृतक कृषि जनजाति का सदस्य था और उसका परिवार पंजाब के प्रथागत कानून द्वारा शासित था। उपर्युक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप यह माना गया कि संपत्ति शुल्क अधिनियम, 1953 (संक्षिप्तता के लिए, 'संपत्ति शुल्क अधिनियम) के तहत संपत्ति शुल्क लगाने के लिए उसकी संपत्ति की गणना करते समय उसकी सभी संपत्तियों के मूल मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। '). आगे की अपील पर अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि क्या मृतक और/या उसके बेटों ने इस प्रथा को छोड़ दिया था, क्योंकि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तराधिकार अधिनियम की घोषणा पर, इस प्रथा को निरस्त कर दिया गया था और कायम रखा गया था। कि इसे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की मृत्यु का मामला माना जाना चाहिए। तदनुसार, मृतक की पूरी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे इस धारणा पर आगे बढ़ना होगा कि यह हिंदू अविभाजित परिवार था और मृतक के हिस्से की सीमा तक, संपत्ति का मूल्यांकन संपत्ति शुल्क अधिनियम की धारा 39 के साथ पठित धारा 7 के तहत किया जा

[11] (1975) 981 ITR. 331 (Punj)

सकता था। राजस्व ने इस न्यायालय का संदर्भ मांगा और निष्कर्ष पैरा में एक डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया है, इस प्रथा को निरस्त नहीं माना जा सकता है और इसे अभी भी प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में एक तथ्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मामले को ट्रिब्यूनल को वापस भेजते समय डिवीजन बेंच के विचार अंतिम पैराग्राफ से समझ में आते हैं, जो इस प्रकार है: -

"पक्षों के वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने पर, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रथा को निरस्त कर दिया गया है और सभी जाटों को हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित किया जाना शुरू हो गया है और उन्होंने अपने बेटों के साथ संयुक्त हिंदू परिवार बनाए और संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक हित रखना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके मामलों में मूल्यांकन अधिनियम की धारा 39 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 के तहत किया जाना था। ये सभी प्रश्न, उदाहरण के लिए, क्या (ए) संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रथा को निरस्त कर दिया गया है, (बी) वह हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित है, (सी) वह अपने बेटों के साथ एक संयुक्त हिंदू परिवार बनाता है, और (डी) संपत्ति में उसका हित एक सहदायिक के रूप में है, इसका निपटारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा पाए गए तथ्य, जो ऊपर दिए गए हैं, मेरे विचार से उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए, हमें संदर्भित कानून के प्रश्न का उत्तर नकारात्मक, यानी विभाग के पक्ष में होना चाहिए।

(20) हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांत ने एक प्रीतम सिंह को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि
प्रीतम सिंह ने संपत्ति शुल्क के प्रयोजनों के लिए इस तर्क पर अपना रिटर्न दाखिल किया था कि उनके पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति एक सहदायिक संपत्ति थी और वह उनके और उनके भाई के साथ हिंदू अविभाजित परिवार का गठन करते थे, इसलिए, संपत्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा ही संपत्ति शुल्क के अधीन करने की पेशकश की गई थी। हालाँकि, हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर, एस्टेट ड्यूटी नियंत्रक ने एस्टेट ड्यूटी अधिनियम की धारा 59 के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि केवल इसलिए उत्तराधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रथा को निरस्त कर दिया गया है और किसानों को हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित किया जाना शुरू हो गया है। तदनुसार, प्रीतम सिंह को संपत्ति शुल्क के मूल्यांकन योग्य संपत्ति के सभी खातों को दाखिल करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि केवल एक/तिहाई हिस्से का मूल्यांकन किया जा सकता था, बाकी को बिना मूल्यांकन के छोड़ दिया गया था। इसके चलते संपत्ति शुल्क अधिनियम की धारा 59 के तहत जारी नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना के साथ एक रिट याचिका दायर की गई। प्रीतम सिंह की ओर से यह तर्क दिया गया कि हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में लिया गया दृष्टिकोण गलत था और हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय संपत्ति शुल्क अधिनियम की धारा 59 के तहत नोटिस जारी करने के प्रयोजनों के लिए जानकारी नहीं बन सकता है। उठाया गया महत्वपूर्ण तर्क यह था कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के आधार पर, प्रथा को निरस्त कर दिया गया है और उत्तराधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सिख हिंदू हैं। एक और तर्क उठाया गया कि प्रथा को उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जाना चाहिए जो इसकी वकालत करता है और इसलिए, संपत्ति शुल्क नियंत्रक किसी भी प्रथा को तथ्य के रूप में साबित करने के लिए बाध्य था। पूर्ण पीठ ने विभिन्न आधारों पर हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया-

(ए) संपत्ति शुल्क अधिनियम की धारा 64 के तहत दिए गए संदर्भ में उच्च न्यायालय की शक्ति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने की है और इसलिए, रिमांड आदेश कानून द्वारा आवश्यक नहीं था; और (बी) यह आगे माना गया कि हरबंस सिंह के मामले में दिए गए निर्देश (सुप्रा) कि निर्धारिती को यह साबित करना होगा कि प्रथा को उसके द्वारा निरस्त कर दिया गया है और वह हिंदू कानून के मिताक्षरा स्कूल द्वारा शासित था और वह
उन्होंने अपने बेटों के साथ एक संयुक्त हिंदू परिवार बनाया, जिसे उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के स्पष्ट प्रावधानों और लाहौर उच्च न्यायालय के कई फैसलों के खिलाफ माना गया, जिसमें मामले में **फातिमा बीबी बनाम शाह निवाज[12] , मोहम्मद जान बनाम रफी-उद-दीन[13] , बलदेव सहाय बनाम राम चंदर[14] , और दया राम बनाम सोहेल सिंह[15]** फैसले भी शामिल थे। इसने यह भी बताया कि निर्धारिती का मामला यह है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 ने उत्तराधिकार के मामले में प्रथा को निरस्त कर दिया था और इसलिए, वे हिंदू कानून द्वारा शासित थे, जो उनका व्यक्तिगत कानून था। पूर्ण पीठ ने यह भी बताया कि चूंकि मामला पक्षों की सहमति के अनुसार ट्रिब्यूनल को भेजा गया था, इसलिए, उच्च न्यायालय को भेजे गए कानून के प्रश्न का उत्तर देने का कोई अवसर नहीं था। तदनुसार, हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में अपनाए गए दृष्टिकोण को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि निर्णय ने उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधानों के आलोक में कोई नया सिद्धांत नहीं दिया है, जो 17 जून, 1956 को लागू हुआ था।

(21) पूर्ण पीठ ने उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले पंजाब राज्य में जाट सिखों सहित कृषि जनजातियों को नियंत्रित करने वाले कानून या/और रीति-रिवाज और उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद कानून की स्थिति पर चर्चा की। पहला प्रस्ताव जो पंजाब कानून अधिनियम, 1872 की धारा 5 के आधार पर निकाला जा सकता है, वह यह था कि व्यक्तिगत कानून को छोड़कर किसी प्रथा के अस्तित्व के पक्ष में कोई धारणा नहीं थी और यदि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि वह या कोई अन्य व्यक्ति प्रथा द्वारा शासित है तो उसे दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि कथित प्रथा ठोस सबूत है। दूसरे शब्दों में, यदि सिद्ध हो जाता है, तो इस प्रथा को इस मुद्दे पर शासन करना था अन्यथा हिंदू कानून को निर्णय का नियम बनना था और उत्तराधिकार के मामले में इसे जाट सिखों पर लागू करना था। पूर्ण पीठ ने अपने फैसले के पैरा 18 में कृषकों के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया। इसके बाद पैरा 19 में मिताक्षरा और दयाभाग प्रणाली पर चर्चा की गई, जो 17 जून, 1956 से पहले अस्तित्व में थी; पैरा 20 में, अपवित्र विधवा को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार और धर्म परिवर्तन के परिणाम; और पैरा 21, 22 और 23 में संयुक्त और अविभाजित हिन्दु परिवार की अवधारणा।

(22) पैरा 24 से पैरा 31 तक, यह उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा लाए गए आमूल-चूल परिवर्तनों के सभी विवरणों में शामिल है। पैरा 32 में उत्तराधिकार अधिनियम से पहले और उसके बाद की पूरी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है

---

[12] AIR 1921 Lahore 180
[13] AIR 1949 P.C 70
[14] 1931 I.L.R. 13 Lahore 126
[15] 110 Punjab Records 1906 (F.B)

"32. इसलिए, कानूनी स्थिति यह उभरती है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने से पहले, जहां पक्षकार हिंदू थे, हिंदू कानून उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में पहली बार लागू होता था, और
जो कोई भी हिंदू कानून के विपरीत किसी प्रथा पर जोर देता है, उसे इसे साबित करना होगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो निर्णय का नियम पार्टियों का व्यक्तिगत कानून होना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून, 1956 से लागू हुआ, और इसकी धारा 4 हिंदू कानून के किसी भी पाठ, नियम या व्याख्या या किसी भी प्रथा या उपयोग को इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले किसी भी संबंध में निरस्त कर देती है। वे मामले जिनके लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर पंजाब कृषि प्रथा की धारा 4 जो अब तक उत्तराधिकार के मामलों में हिंदुओं पर लागू होती थी, उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और अब कोई भी हिंदू संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित नहीं होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद, सभी हिंदू, जैसा कि उस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है, उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू कानून और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने संयुक्त को समाप्त नहीं किया है हिंदू परिवार और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति और यह उन लोगों के विशेष अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता है जो मिताक्षरा सहदायिकी के सदस्य हैं, अधिनियम की धारा 6 और 30 में उल्लिखित तरीके और सीमा को छोड़कर। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, सभी हिंदू जो पहले उत्तराधिकार के मामलों में प्रथागत कानून के नियमों द्वारा शासित होते थे, अन्य हिंदुओं की तरह, मिताक्षरा सहदायिक सहित संयुक्त और अविभाजित हिंदू परिवार और उनके बेटे, पोते और परपोते शामिल हो गए। कुछ समय के लिए संयुक्त या सहदायिक संपत्ति का धारक, जन्म से उसमें ब्याज प्राप्त करता है।

(23) मिताक्षरा सहदायिकी के सिद्धांत हिंदू कानून न्यायशास्त्र में अंतर्निहित हैं और 1956 अधिनियम के बाद भी लागू होते रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग को मान्यता दी है। इस संबंध में **धर्मा शामराव अगलावे बनाम पांडुरंग मिरागु अगलावे,**[16] **और शीला देवी बनाम लाई चंद**[17] के मामलों में दो निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है। हालाँकि, इन सिद्धांतों का अधिक स्पष्ट कथन, जैसा कि प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा मान्यता प्राप्त है, आस **कौर बनाम करतार सिंह**[18] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मताक्षरा सहदायिकता के सिद्धांतों के अस्तित्व को यह कहते हुए दोहराया कि पैतृक पूर्वज से विरासत में मिली संपत्ति, प्रस्ताव के पुरुष मुद्दे के संबंध में निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति है, लेकिन अन्य संबंधों के संबंध में यह उनकी पूर्ण संपत्ति है।' देयर लॉर्डशिप्स ने प्रसिद्ध ग्रंथ मुल्ला के सिद्धांतों के हिंदू कानून (15 वें संस्करण, पृष्ठ 289 पर) से निम्नलिखित कथन को सारगर्भित किया है।
".....यदि किसी को अपने पिता या पिता के पिता, पिता के पिता के पिता से संपत्ति विरासत में मिलती है, चाहे वह चल हो या अचल, यह उसके पुरुष मुद्दे के संबंध में पैतृक संपत्ति है। यदि ए के पास उस समय कोई बेटा, बेटे का बेटा, या बेटे के बेटे का बेटा अस्तित्व में नहीं है जब उसे

---

[16] (1988) 2 S.C.C. 126
[17] (2006)8 S.C.C. 581
[18] **(2007)5 S.C.C. 561**

संपत्ति विरासत में मिली है, तो वह संपत्ति को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में रखता है और वह इसके साथ अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है.....
एक व्यक्ति जिसे अपने तीन निकटतम पूर्वजों से संपत्ति विरासत में मिलती है, वह इसे अपने पुत्रों, पुत्रों के पुत्रों और पुत्र के पुत्रों के पुत्रों के साथ सहदायिक रूप में धारण करता है, और इसे धारण करना ही चाहिए, लेकिन
जहां तक अन्य संबंधों का संबंध है, वह इसे अपने पास रखता है और अपनी पूर्ण संपत्ति के रूप में इसे रखने का हकदार है।''
दोबारा:
पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर एक सहदायिक को जो हिस्सा मिलता है, वह उसके पुरुष मुद्दे के संबंध में पैतृक संपत्ति है। वे इसमें जन्म से ही रुचि लेते हैं, चाहे वे विभाजन के समय अस्तित्व में हों या उसके बाद पैदा हुए हों। हालाँकि, ऐसा हिस्सा केवल उसके पुरुष मुद्दे के संबंध में पैतृक संपत्ति है। जहां तक अन्य संबंधों का संबंध है, यह अलग संपत्ति है, और यदि सहदायिक की बिना पुरुष संतान छोड़े मृत्यु हो जाती है, तो यह उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाती है।'' यह देखा गया कि कानून के उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में कोई विवाद नहीं है और धर्म शामराव अगलावे (सुप्रा) और शीला देवी (सुप्रा) [सी.एफ.] के मामलों में निर्णयों पर भी भरोसा किया। **धन कर आयुक्त बनाम चंदर सेन,[19] और माखन सिंह बनाम कुलवंत सिंह**,[20] ।

(24) हम प्रीतम सिंह के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए प्रस्ताव को यह कहकर सारांशित कर सकते हैं कि उत्तराधिकार अधिनियम ने उन लोगों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त हिंदू परिवार को समाप्त नहीं किया है जो मिताक्षरा सहदायिक के सदस्य हैं, सिवाय इसके कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 30 में उल्लिखित तरीके से और सीमा तक। इस कथन का यह भी अर्थ होना चाहिए, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता है, इस सीमा तक उत्तराधिकार अधिनियम दयाभागा सहदायिकी द्वारा शासित सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

(25) एक बार यह स्थापित हो जाए कि उत्तराधिकार अधिनियम मितकाशारा सहदायिकी के सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है (निश्चित रूप से 2005 के संशोधन अधिनियम से पहले)। चूँकि, तथ्यों के आधार पर, कोई महिला उत्तराधिकारी नहीं थी या महिला के माध्यम से कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, जैसा कि 1995 के मूल अधिनियम की असंशोधित धारा 6 की गोपनीयता के तहत परिकल्पित किया गया था, पूरी संपत्ति केवल जीवित रहने के आधार पर बेटों में निहित रहेगी। हम यह भी देख सकते हैं कि धारा 14 और 30 की तुलना करने पर यह तर्क देना संभव है कि उत्तराधिकार अधिनियम ने न केवल 7 जून, 1956 के बाद (2005 के संशोधित अधिनियम से पहले) उसकी संपत्ति में महिला हितों को बढ़ाया, बल्कि यह धारा 30 के आधार पर एक पुरुष धारक को भी उसके अपने हिस्से के संबंध में उसके साथ बराबरी पर ले आया। (26) इसके अलावा, सहदायिकता की अवधारणा पंजाब के जाट कृषकों के लिए अलग नहीं है क्योंकि वे पैतृक संपत्ति की भी बात करते थे (सहदायिकता का मुख्य आधार - पृष्ठ 356 पर पैरा 22 देखें), जैसा कि स्व-अर्जित संपत्ति से अलग है, और

---

[19] AIR 1986 S.C. 1753
[20] AIR 2007 S.C. 108

जैसा कि हिंदू कानून में किया जाता है, पांच डिग्री के संदर्भ में उलटने वालों की पहचान की जाती है, संदर्भ में उल्लिखित भेद का बिंदु गायब हो जाता है।

(27) प्रीतम सिंह के मामले में पूर्ण पीठ ने जोगिंदर सिंह के मामले में पिछली पूर्ण पीठ के फैसले पर स्पष्ट रूप से गौर किया लेकिन
इसे यह देखते हुए अप्रासंगिक माना गया कि यह प्रथागत कानून द्वारा शासित किसी व्यक्ति की हस्तांतरण की शक्ति और उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की संवैधानिक वैधता (पृष्ठ 360 पर पैरा 33) से संबंधित है। हमारी ओर से यह व्यापक बयान देना संभव नहीं है कि उत्तराधिकार का हस्तांतरण से कोई लेना-देना नहीं है या इसके विपरीत। उत्तराधिकार और हस्तांतरण की दोनों अवधारणाओं को निर्विवाद डिब्बे में नहीं रखा जा सकता है। यह देखा गया है कि अधिकांश अवसरों पर हस्तांतरण का मुद्दा उत्तराधिकार और विरासत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। विरासत में मिली संपत्ति की प्रकृति हस्तांतरण के परिणामों को प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए, यदि उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद हिंदू महिला द्वारा विरासत में मिली संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है, तो उस मामले की तुलना में अलग-अलग परिणाम होंगे जहां स्थानांतरण सहदायिक संपत्ति के पुरुष धारक द्वारा किया जाता है। पहले मामले में, प्रत्यावर्तक महिला मालिक की मृत्यु से पहले या बाद में हस्तांतरण को चुनौती देने का हकदार नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे मामले में पुरुष स्वामी की मृत्यु के बाद प्रत्यावर्तनकर्ता द्वारा हस्तांतरण को चुनौती दी जा सकती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रीतम सिंह के मामले में पूर्ण पीठ ने हस्तांतरण से निपटने के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि प्रीतम सिंह के मामले में संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के प्रयोजनों के लिए संपत्ति की विरासत का प्रश्न शामिल था, जो परिणामस्वरूप यह प्रश्न तय हो गया कि क्या अपने पिता की मृत्यु के बाद जवाबदेह व्यक्तियों के हाथ में पूरी संपत्ति प्रथागत कानून द्वारा शासित पैतृक संपत्ति थी या यह हिंदू कानून द्वारा शासित सहदायिक संपत्ति थी, जबकि जोगिंदर सिंह के मामले में, तीसरे के कहने पर पिता द्वारा अपने दो बेटों के पक्ष में की गई सहमति डिक्री द्वारा हस्तांतरण की वैधता को चुनौती दी गई थी। नतीजतन, जोडिंगर सिंह के मामले में यह माना गया कि 17 जून, 1956 से उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पुरुष मालिक की संपत्ति में उस तरह से वृद्धि नहीं हुई है, जिस तरह से उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत एक महिला मालिक की संपत्ति में वृद्धि हुई है। हस्तांतरण के संबंध में उसकी शक्ति पर सभी सीमाएं उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा किसी भी तरह से नहीं हटाई गईं। जोगिंदर सिंह के मामले में निर्णय द्वारा निर्धारित कई अन्य प्रस्ताव पहले ही पैरा संख्या 14 में देखे जा चुके हैं। संभवतः चूंकि हस्तांतरण स्ट्रिक्टोसेन्सो से संबंधित मुद्दा प्रीतम सिंह के मामले में पूर्ण पीठ के समक्ष नहीं था, इसलिए उसने इससे निपटना पसंद नहीं किया।

(28) हमारे लिए हस्तांतरण से संबंधित कानून के इतिहास का संदर्भ देना उचित होगा, जिसका पता 1872 में लगाया जा सकता है जब पंजाब कानून अधिनियम, 1872 लागू किया गया था। देशी कानून को निर्णयों का नियम बनाने के प्रयास में, 1872 अधिनियम की धारा 5 में निम्नानुसार घोषित किया गया: -

"5. कुछ मामलों में निर्णय देशी कानून के अनुसार होंगे।-
उत्तराधिकार, महिलाओं की विशेष संपत्ति, सगाई, विवाह, तलाक, मेहर, गोद लेने, संरक्षकता, अल्पसंख्यक, कमीनेपन, पारिवारिक संबंध, वसीयत, विरासत, उपहार, विभाजन, या किसी धार्मिक उपयोग या संस्था से संबंधित प्रश्नों में, निर्णय का नियम होगा :

(ए) संबंधित पक्षों पर लागू कोई भी प्रथा, जो न्याय, समानता या अच्छे विवेक के विपरीत नहीं है, और इस या किसी अन्य अधिनियम द्वारा बदला या समाप्त नहीं किया गया है, और किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है;
(बी) मोहम्मडन कानून, उन मामलों में जहां पार्टियां मोहम्मडन हैं और हिंदू कानून, ऐसे मामलों में जहां पार्टियां और हिंदू, सिवाय इसके कि ऐसे कानून को विधायी अधिनियम द्वारा बदल दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है, या इस अधिनियम के प्रावधानों का विरोध किया गया है , या ऐसी किसी प्रथा द्वारा संशोधित किया गया है जैसा कि ऊपर बताया गया है।"

(29) उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि संपत्ति के विभिन्न स्वभाव से संबंधित प्रश्न, जहां पक्षकार हिंदू थे, वहां हिंदू कानून लागू किया गया था, सिवाय इसके कि इस तरह के कानून को विधायी अधिनियमन द्वारा बदल दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है या
1872 के अधिनियम के प्रावधानों का विरोध किया गया था। उप-खंड (ए) के अनुसार, पार्टियों पर लागू होने वाली कोई भी प्रथा निर्णय का नियम होगी, बशर्ते कि यह न्याय, समानता या अच्छे विवेक के विपरीत न हो और किसी भी कानून द्वारा परिवर्तित या समाप्त नहीं किया गया हो या शून्य घोषित न किया गया हो। कोई सक्षम प्राधिकारी दूसरे शब्दों में, रीति-रिवाज को गैर-संहिताबद्ध हिंदू कानून पर प्राथमिकता दी गई, संभवतः इस कारण से कि प्रथा लगातार हिंदू कानून की जगह ले रही है। हालाँकि, यह जल्द ही महसूस किया गया कि पैतृक अचल संपत्ति, जिसे आम तौर पर पंजाब के जाटों के बीच आवश्यकता को छोड़कर रीति-रिवाज के आधार पर अविभाज्य माना जाता था, इस तरह के हस्तांतरण का मुकाबला करने के लिए संपार्श्विक की डिग्री पर कोई सीमा नहीं रखी गई थी। इसलिए, हस्तांतरण का मुकाबला करने के लिए पात्र संपार्श्विक की डिग्री पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक महसूस किया गया, जो कि प्रथा के तहत सीमित नहीं था। तदनुसार, पंजाब कस्टम (प्रतिद्वंद्विता की शक्ति) अधिनियम, 1920 (1920 का अधिनियम संख्या 2) अधिनियमित किया गया था। उत्तराधिकार अधिनियम को पंजाब राज्य तक विस्तारित किया गया। धारा 2 संपत्ति के किसी भी वसीयतनामा स्वभाव को शामिल करने के लिए अभिव्यक्ति 'हस्तांतरण' को परिभाषित करती है और उत्तराधिकारी की नियुक्ति में रीति-रिवाज के अनुसार किया गया कोई भी गोद लेना या किए जाने का इरादा शामिल है। धारा 3 द्वारा एक और प्रावधान किया गया था कि उत्तराधिकार अधिनियम केवल अचल संपत्ति के हस्तांतरण या उन व्यक्तियों द्वारा किए गए उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में लागू होगा जो इस तरह के स्थानांतरण या नियुक्ति के संबंध में रीति-रिवाजों द्वारा शासित थे, जबकि धारा 4 में घोषित किया गया कि उत्तराधिकार अधिनियम उस तारीख से पहले किए गए किसी भी हस्तांतरण या उत्तराधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिस दिन उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना था। दूसरे शब्दों में, 1920 का अधिनियम संख्या 2 अपने लागू होने की तारीख से पहले किए गए हस्तांतरण या वारिस की नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। इसने किसी परिवार द्वारा किए गए किसी भी हस्तांतरण या उत्तराधिकारी की नियुक्ति के अधिकारों को भी संरक्षित किया। 1920 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा अधिनियमित धारा 6 और 7 को पढ़ना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:-
"**6. हस्तांतरण और विरासत की नियुक्ति का मुकाबला करने के अधिकार पर सीमा**। - धारा 4 में निहित प्रावधानों के अधीन और धारा 5, पंजाब कानून अधिनियम, 1872 में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति पैतृक अचल संपत्ति या किसी अन्य के हस्तांतरण

का विरोध नहीं करेगा। ऐसी संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि ऐसा स्थानांतरण या नियुक्ति लागत के विपरीत है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति स्थानांतरण या नियुक्ति करने वाले व्यक्ति के परदादा के पुरुष वंश में न हो।
"**7. गैर-पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण** - धारा 5, पंजाब कानून अधिनियम, 1872 में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति गैर-पैतृक अचल संपत्ति के हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति के लिए किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति का इस आधार पर विरोध नहीं करेगा कि ऐसा हस्तांतरण या नियुक्ति रीति-रिवाज के विपरीत है।"

(30) यह तत्कालीन पंजाब राज्य में प्रचलित स्थिति थी, जिसे 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और फिर पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा विभाजन के अधीन किया गया था।
(31) पंजाब राज्य द्वारा अनेक सुधार किये गये इसके परिणामस्वरूप पंजाब प्रीएम्प्शन (निरसन) अधिनियम, 1973 द्वारा प्री-एम्प्शन के अधिकार को समाप्त करने के अलावा, 1920 के अधिनियम संख्या 2 की धारा 6 और 7 में संशोधन किया गया है। तदनुसार, आरंभ करने के लिए, पंजाब कस्टम (चुनाव लड़ने की शक्ति) संशोधन (1973 का पंजाब अध्यादेश 2), 23 जनवरी, 1973 से प्रख्यापित किया गया था, जो बाद में इसे 1973 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जैसा कि 9 अप्रैल, 1973 को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। संशोधन का प्रभाव यह है कि 1920 के अधिनियम संख्या 2 की धारा 6 को हटा दिया गया है और संशोधन के बाद धारा 7, जैसा कि अब मौजूद है, इस प्रकार है: -
"7. गैर-पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण - धारा 5, पंजाब कानून अधिनियम, 1872 में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण, चाहे वह पैतृक हो या गैर-पैतृक हो, ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर इस आधार पर विरोध नहीं करेगा कि ऐसा स्थानांतरण या नियुक्ति रीति-रिवाज के विपरीत है।"

(32) उपरोक्त स्थिति को दर्शन सिंह के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा देखा गया है, जिस पर वरिष्ठ वकील श्री एम.एल. सरीन ने दृढ़ भरोसा जताया है। दर्शन सिंह के मामले में, 22 अगस्त, 1966 को एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी के प्रथागत गोद लेने और उसके पक्ष में किए गए उपहार विलेख को चुनौती दी गई थी। यह दावा किया गया था कि वादी अपने पक्ष में संपत्ति के परिवर्तन का हकदार था। मुकदमे का फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा 16 अक्टूबर, 1968 को किया गया और पहली अपील पर, जिला न्यायाधीश ने 12 जनवरी, 1970 को मामले को वापस भेज दिया। रिमांड के बाद ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त, 1971 को फैसला सुनाया। फिर से जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की गई, जिन्होंने 28 फरवरी, 1973 को इसका निपटारा कर दिया। इस बीच, संशोधन अधिनियम 1973 23 जनवरी, 1973 को लागू हुआ। दूसरी अपील 25 मार्च, 1973 को दायर की गई और इसे 3 अप्रैल, 1973 को खारिज कर दिया गया। इस प्रश्न पर कि 1973 का संशोधन अधिनियम लागू होना चाहिए या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने यह माना कि किसी भी व्यक्ति को 23 जनवरी, 1973 के बाद प्रथा के विपरीत होने के आधार पर अचल संपत्ति, चाहे पैतृक हो या गैर-पैतृक, के किसी भी हस्तांतरण का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। संशोधन अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित धारा 7 सभी लंबित कार्रवाइयों पर लागू होनी थी, चाहे मुकदमे के चरण में या अपीलीय न्यायालय के समक्ष। अपनाया गया तर्क यह है कि अपील

मुकदमे की निरंतरता है और यदि कस्टम के विपरीत होने के आधार पर हस्तांतरण को चुनौती देने का अधिकार छीन लिया गया है तो पहली या दूसरी अपील के चरण में भी चुनाव लड़ने का ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आगे यह माना गया है कि संशोधन अधिनियम, 1973 ने पैतृक या गैर-पैतृक अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है कि ऐसा स्थानांतरण या नियुक्ति रीति-रिवाज के विपरीत है। आगे यह माना गया है कि संशोधित धारा 7 में प्रयुक्त भाषा इस प्रथा के निरंतर अस्तित्व के अनुरूप है। उनके आधिपत्य ने धारा 7 में प्रयुक्त शब्दों पर जोर दिया यानी 'कोई भी व्यक्ति इस आधार पर किसी हस्तांतरण का विरोध नहीं करेगा कि ऐसा हस्तांतरण प्रथा के विपरीत है' और उपरोक्त अभिव्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना। आगे यह माना गया है कि संशोधित प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से अनिवार्य रूप से यह परिणाम निकलेगा कि प्रथा के विपरीत होने के कारण प्रतियोगिता का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और छीन लिया गया है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को 23 जनवरी, 1973 के बाद प्रथा के विपरीत होने के आधार पर अचल संपत्ति, चाहे वह पैतृक हो या गैर-पैतृक, के किसी भी हस्तांतरण का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।

(33) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराधिकार के संबंध में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 के सर्वव्यापी प्रभाव को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में मान्यता दी गई है। धारा 2 में परिभाषित पंजाब कृषि प्रथा अब तक हिंदुओं पर लागू नहीं थी, जो उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। उस संबंध में **तारो बनाम दर्शन सिंह,[21] हंस राज बसंत राम बनाम धनवंत सिंह बलवंत सिंह[22] बंसो बनाम चरण सिंह,[23] कालू बनाम नंद सिंह,[24] और कौर सिंह गज्जन सिंह** (सुप्रा)।

(34) हरियाणा में, 1920 के अधिनियम संख्या 2 द्वारा प्रतिपादित स्थिति हस्तांतरण के संबंध में बनी रही क्योंकि 1973 के संशोधन अधिनियम द्वारा लाए गए पंजाब के समानांतर कोई सुधार नहीं किया गया है, हालांकि पूर्व-मुक्ति का अधिकार है हरियाणा में भी काफी हद तक खत्म कर दिया गया है. विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संबंध में कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। इसलिए, हरियाणा की स्थिति को 1920 के अधिनियम संख्या 2 के तहत मौजूद माना जाना चाहिए।

(35) इस प्रश्न का कि क्या जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) और प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों के बीच कोई विरोधाभास है, का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए, जैसा कि श्री एम.एल. ने सुझाव दिया है। सरीन और श्री एस.डी. शर्मा, विद्वान वरिष्ठ वकील। 28 अगस्त, 1981 के संदर्भ आदेश के अवलोकन से एक विद्वान वकील की यह दलील भी सामने आई कि कोई विवाद नहीं है। अपनी ओर से हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए सहमत हैं कि विभिन्न कारणों से दो पूर्ण पीठ के निर्णयों के बीच कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं है: -

---

[21] AIR 1960 Pun] 145
[22] AIR 1961 Pun] 510
[23] AIR 1961 Punj 45
[24] AIR 1974 P&H. 50

(i) पूर्ण पीठ के दोनों फैसले इस धारणा पर दिए गए हैं कि जोगिंदर सिंह का मामला (सुप्रा) हस्तांतरण के सवाल से निपटता है जबकि प्रीतम सिंह का मामला (सुप्रा) उत्तराधिकार से संबंधित सवाल का फैसला करता है। उपर्युक्त निष्कर्ष को प्रीतम सिंह के मामले (सुप्रा) में व्यक्त राय द्वारा समर्थित किया गया है, जब पैरा 33 में उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा है: - "....उनके द्वारा उद्धृत कोई भी निर्णय मुद्दे के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। उनके द्वारा उद्धृत निर्णय गुजरवर्सस शाम दास (110 पी.आर. 1887), जेकनवाला बनाम हीरा सिंह (55 पी.आर. 1903), रोडा, हीरा और अन्य बनाम हमाम (18 पी.आर. 1895), और कमाल सिंह और अन्य बनाम नौनिहाल सिंह (एआईआर 1945 लाहौर 188)), एक पुत्रहीन मालिक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण की शक्तियों से निपटता है और सुंदर बनाम सालिग राम और अन्य (26 पी.आर. 1911), प्रथागत कानून द्वारा शासित एक विधवा के हस्तांतरण की शक्तियों से निपटता है। जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम केहर सिंह (एआईआर 1965 पंजाब 407) में निर्णय भी अप्रासंगिक है क्योंकि यह प्रथागत कानून और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 द्वारा शासित व्यक्ति के हस्तांतरण की शक्तियों से संबंधित है। प्रतिवादी के वकील द्वारा मुद्दे से संबंधित किसी निर्णय का हवाला नहीं दिया गया..."

(ii) तथ्यों पर भी हम पाते हैं कि जोगिंदर सिंह के मामले में मुद्दा एक पिता द्वारा अपने दो बेटों के लिए सहमति डिक्री द्वारा हस्तांतरण की वैधता था, जिसे तीसरे बेटे ने चुनौती दी थी, जबकि प्रीतम सिंह के मामले में संपत्ति शुल्क के आकलन के उद्देश्य से पिता की मृत्यु पर बेटों के हाथ में संपत्ति की प्रकृति का प्रश्न उठा था। प्रीतम सिंह के मामले में बेटों के हाथ की संपत्ति को सहदायिक संपत्ति माना गया और मृत पिता की संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही संपत्ति शुल्क के लिए योग्य माना गया। इसलिए, प्रीतम सिंह के मामले में हस्तांतरण का कोई सवाल ही नहीं था।

(iii) प्रीतम सिंह के मामले में पूर्ण पीठ गठित करने की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हरबंस सिंह के मामले (सुप्रा) में एक डिवीजन बेंच के फैसले में गलत धारणा दी गई है कि सहदायिक की मृत्यु के बाद संपत्ति जाट सिखों के हाथों में थी। इसे पैतृक संपत्ति माना जाएगा क्योंकि यह प्रथा पंजाब के जाट सिखों पर शासन करती रही, जो एक कृषि प्रधान समुदाय है। उस दृष्टिकोण को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

(36) प्रश्न संख्या 1 पर उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि जोगिंदर मामले में दिए गए पूर्ण पीठ के निर्णयों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। सिंह का मामला (सुप्रा) और प्रीतम सिंह का मामला (सुप्रा) क्योंकि एक मामले में अदालत को संपत्ति के हस्तांतरण के मुद्दे पर निर्णय लेने से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी और दूसरे मामले में मुद्दा पूरी तरह से उत्तराधिकार के सवाल पर निर्भर था। हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि यद्यपि हस्तांतरण का मुद्दा किसी भी स्थिति में उत्तराधिकार के मुद्दे पर प्रभाव डाल सकता है, फिर भी तथाकथित संघर्ष की स्थिति में, कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि जोगिंदर सिंह के मामले में हस्तांतरण का मुद्दा अंततः उत्तराधिकार के मुद्दे को गले नहीं लगा सका (सुप्रा)।

(37) दूसरे प्रश्न का उत्तर दो भागों में देना है. पंजाब राज्य के संबंध में पंजाब संशोधन अधिनियम, 1973 के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि पैतृक या गैर-पैतृक अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या नियुक्ति या ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी को इस आधार पर चुनौती देने पर पूर्ण प्रतिबंध है। हस्तांतरण या नियुक्ति प्रथा के विपरीत थी। उपरोक्त विस्तृत चर्चा के साथ-साथ **दर्शन सिंह** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हालाँकि, पंजाब में उत्तराधिकारी के हाथ में मौजूद संपत्ति को सहदायिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और इसके हस्तांतरण को हिंदू

कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और 30 द्वारा विनियमित है।

(38) हरियाणा में, उत्तराधिकारी के हाथ में मौजूद संपत्ति को प्रथागत कानून के अनुसार सहदायिक संपत्ति के साथ-साथ पैतृक संपत्ति भी माना जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि पक्ष परंपरा में निर्णय के नियम को स्थापित करने में विफल रहते हैं तो वे हिंदू कानून का सहारा ले सकते हैं। इसलिए, हरियाणा में हिंदू कानून और प्रथागत कानून दोनों के तहत, हस्तांतरण को चुनौती दी जाएगी। उन सभी स्थितियों पर विचार करना आसान नहीं है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर हस्तांतरण के संबंध में प्रथागत कानून के विपरीत हिंदू कानून के आवेदन से उभरेंगी।

(39) तदनुसार, संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है। अब सभी अपीलों को यहां निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh